

केंद्रीय एक्साइज आयुक्त, जयपुर

बनाम

मैसर्स राजस्थान एसपीजी और डब्ल्यूवीजी मिल्स लिमिटेड व अन्य

नवंबर 28,2007

[न्यायमूर्ति एसएच कपाडिया, बी. सुदर्शन रेड्डी]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियम, 1975:

आरआर 6 (ख) (i), (ii) और 7-निर्धारण योग्य मूल्य -गणना -बुनाई इकाई पर तैयार किया गया कपड़ा -प्रसंस्करण गृह में कार्य के आधार पर तैयार -प्रसंस्करण गृह से अवर्गीकृत माल प्राप्त किया गया -निर्माता वर्गीकृत माल का काम कर था और उसके बाद डिपो द्वारा माल क्लियर किया गया -राजस्व द्वारा अंतर शुल्क का दावा इस आधार पर की प्रसंस्करण हेतु पट्टा करार एक धोखा था ताकि प्रसंस्कृत कपड़े के मूल्यांकन को " तुलनीय माल विधि "से" लागत विधि " में बदला जा सके! अधिकरण द्वारा पट्टा करार को वास्तविक/असली माना और निर्माता लागत विधि को नियम 6(b)(2) के अधीन इन्वोक करने में सही है! अभिनिर्धारित किया गया: वर्गीकृत माल जो डिपो से क्लियर किया गया, का मूल्य अवर्गीकृत माल जो कि फैक्ट्री से निकाला गया से भिन्न होगा -इस प्रकार इसको ध्यान में रखते हुए बेचे गए श्रेणीबद्ध कपड़े की आनुपातिक वास्तविक वसूली राजस्व द्वारा आंकलित से ज्यादा होगी -एक

सामान्य मूल्यांकन के लिए अलग -अलग विधियों का अनुसरण करना पडा  
-अनुसरण का पहलू महत्वपूर्ण है -गणना में ज्यादा उतार -चढाव को  
स्वीकार नहीं किया जा सकता -राजस्व मूल्यांकन के लिए अलग -अलग  
विधियों को अपना सकता है पर इनको अंततः अभिसरण का नियम का  
प्रयोग करते हुए मूल्य की गणना करनी पड़ेगी ताकि निर्धारण योग्य मूल्य  
की गणना की जा सके -न्यायाधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करने का  
कोई आधार नहीं है!

उजागर प्रिंट्स और अन्य बनाम. भारत संघ और अन्य। , [1989]

3 एससीसी 531, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 735-744/2002

अंतिम आदेश सं. 134-43/2001-ए दिनांकित 4.4.2001 सीमा  
शुल्क, उत्पाद और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली  
अपील सं. ई/489-498/2000-ए,

के साथ

सीएस. 8671-8672/2002 और 2624/2003

आर. जी. पाडिया, टी. वी. रत्नम, बी. के. प्रसाद और ललित  
श्रीवास्तव (अपीलार्थी के लिए)

लक्ष्मी कुमारन, आलोक यादव, वीण् बालचंद्रन, राजेश कुमार और  
एम. पी. देवनाथ (प्रत्यर्थीगण के लिए)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया था

### आदेश

1. विभाग द्वारा दायर दीवानी अपीलों के समूह को सी.ई.जी.ए.टी. (नई दिल्ली अपील संख्या ई/489-498/2000-ए) द्वारा पारित दिनांक 4 अप्रैल, 2001 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।

2. अधिकरण के समक्ष निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु यह था कि क्या राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड (आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल.) वास्तविक निर्माता था जो प्रसंस्करण गृह, मोरडी से कपड़ा प्रसंस्करण करता था और यदि था तो क्या विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) 1975 (संक्षेप में 1975 के नियम) के नियम 7 का प्रयोग करते हुए सर्वोत्तम मूल्यांकन करने में सही था।

3. आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. सूत और कपड़े के निर्माता हैं। इन्होंने 1994-95 में मोर्डि में एक प्रसंस्करण गृह की स्थापना की थी। प्रसंस्करण गृह की स्थापना कपड़े के प्रसंस्करण के लिए की गई थी। उनके बुनाई से बने बुने हुए कपड़े जो उनकी इकाई पर तैयार किए जाते थे, मोर्डि प्रसंस्करण गृह द्वारा कार्य के आधार पर प्रसंस्कृत किए जाते थे। यह 29 मार्च, 1995 से प्रभावी हुआ था। 16 जून, 1995 को उक्त प्रसंस्करण गृह आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. एल द्वारा भीलवाड़ा स्पिनर्स लिमिटेड (बीएसएलड) को पट्टे पर दिया गया था। बाद में आर. एस. डब्ल्यू. एम.

एल. और बीएसएल के बीच पट्टा समझौता समाप्त कर दिया गया और प्रसंस्करण गृह को पूर्वी फैब्रिक्स और टेक्सचर (पी.एफ.टी एल) को पट्टे पर दे दिया गया!

4. उपरोक्त बदलाव पर विभाग को संदेह था। इसलिए विभाग ने 22 सितंबर, 1998 को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया और आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. से 16 जून, 1995 से 20 फरवरी, 1996 तक की अवधि के लिए अंतर शुल्क का दावा इस आधार पर किया कि वास्तविक निर्माता आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. था और उपरोक्त पट्टा करार में बदलाव एक दिखावा क्योंकि कि यह मूल्यांकन के आधार "तुलनीय माल आधारको लागत विधि" में बदला जा सके!

5. तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ऊपर उल्लिखित पट्टा करार वास्तविक था और इसलिए आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. उक्त 1975 के नियम 6 (बी) (II) के तहत लागत विधि को इन्वोक करने में सही था। अधिकरण के अनुसार वर्तमान मामला " उजागर प्रिंट्स एंड अन्य बनाम भारत संघ [1989] 3 एससीसी 531 के इस न्यायालय का निर्णय जैसा है।

6. शुरुआत में हम ध्यान दे सकते हैं कि मूल्यांकन के प्रश्न की जांच अधिकरण द्वारा नहीं की गई। भले ही हम यह धारणा कर आगे बढ़ें कि अधिकरण ने गलती की थी, हम अभी भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के

लिए इच्छुक नहीं है! इसलिए हम इस आधार पर कि आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. वास्तविक निर्माता है और पट्टा एक एक दिखावा थाए आगे बढ़ रहे हैं!

7. यह प्रश्न अभी भी उठेगा कि क्या यदि किसी को "तुलनीय माल पद्धति " के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है तो भी क्या यह कम मूल्यांकन का मामला है। क्या मामला राजस्व तटस्थ है? इस संबंध में, हम बता सकते हैं कि "तुलनीय माल पद्धति " पर नियम 6(बी)(i) द्वारा विचार किया जा सकता है, जबकि "लागत विधि" पर नियम 6(बी)(ii) द्वारा विचार किया जा सकता है। इस मामले में भले ही हम नियम 6(बी) (i) के तहत आगे बढ़ें, जैसा कि विभाग ने तर्क दिया है, हम तथ्यों से पाते हैं कि आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. अपने प्रसंस्करण गृह से अवर्गीकृत कपड़े प्राप्त करता था, उसके बाद आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. उनको वर्गीकृत करने का काम करता था। छँटाई की और उसके बाद माल को उनके डिपो के माध्यम से क्लियर किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के तहत, जैसा कि प्रासंगिक समय पर था, सामान्य कीमत, निर्धारण योग्य मूल्य का आधार बनी। हम यहां नीचे धारा 4(1)(ए) उद्धृत कर रहे हैं:

"4. उत्पाद शुल्क के प्रभार के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन -(1) जहां इस अधिनियम के तहत, मूल्य के संदर्भ में किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। ऐसा मूल्य, अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, यह माना जाएगा-

(ए) उसकी सामान्य कीमत, यानी वह कीमत जिस पर थोक व्यापार के दौरान करदाता द्वारा खरीददार को सामान को हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए खरीददार को आम तौर पर ऐसे सामान बेचे जाते हैं, जहां खरीददार नहीं होता है संबंधित व्यक्ति और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है:"

8. वर्तमान मामले में हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि पूर्व-फैक्टरी कीमत निर्धारित थी। फिर भी, रेखांकित शब्दों से संकेत मिलता है कि यदि आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. के डिपो में वर्गीकृत माल की बिक्री कीमत को ध्यान में रखा जाए तो डिपो में क्लियर किए गए ऐसे माल (वर्गीकृत ) का मूल्य अवर्गीकृत माल के मूल्य से भिन्न होगा। विभाग के

अनुसार एक्स-फैक्ट्री कीमत को ध्यान में रखना आवश्यक था। हालाँकि, विभाग ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया है कि एक ओर फैक्ट्री गेट पर क्लियर किए गए माल में असमानता थी, वह अवर्गीकृत माल था, और दूसरी ओर आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. के सेल्स डिपो में क्लियर किया गया माल वर्गीकृत था। यदि इस अंतर को ध्यान में रखा जाए तो जिसे "मूल्यवर्धन" कहा जाता है। विभाग द्वारा उस मूल्यवर्धन पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिए करनिर्धारिती द्वारा मूल्यवर्धन पर छूट का दावा किया गया था। आयुक्त द्वारा पारित आदेश में मामले के इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं है। उस संबंध में हम आयुक्त के समक्ष आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. द्वारा प्रस्तुत एक पूरी तालिका नीचे उद्धृत कर रहे हैं जो इस प्रकार है:

"यहां तक कि अगर मूल्य तुलनीय वस्तुओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है तो कोई अंतर शुल्क दायित्व नहीं होगा। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:

	मात्रा (मीटर)	मूल्य (रुपए)
52 ए के अनुसार मूल्यांकन योग्य मूल्य 16.6.95 से	17004521	105,53,29,128

20.2.98 की अवधि के लिए		
उत्पाद शुल्क का भुगतान		16,20,17,071
कुल सह शुल्क मूल्य	17004521	121,73,46,199
गांठ और श्रेणीबद्ध कपड़े के बीच मूल्यवर्धन के लिए 40%		48,69,38,480
प्रसंस्कृत कपड़ों की अपेक्षित बिक्री मूल्य	17004521	170,42,84,679
वाणिज्यिक चालान के अनुसार श्रेणीबद्ध कपड़ों की बिक्री पर आनुपातिक वास्तविक प्राप्ति	17004521	167,35,65,236

9. कोई उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करता है तो यह स्पष्ट है कि यदि किसी को नियम 6(बी)(i) के तहत "तुलनीय माल पद्धति" पर मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना करनी है, तो निर्धारिती के अनुसार, गांठदार कपड़े और श्रेणी बद्ध के बीच मूल्यवर्धन हुआ है। श्रेणीबद्ध कपड़ा, यदि उस मूल्यवर्धन को ध्यान में रखा जाए तो श्रेणीबद्ध कपड़ों की बिक्री पर आनुपातिक वास्तविक प्राप्ति 167,35,65,236 करोड़ रुपये होगी, जो कि विभाग द्वारा गणना की गई कीमत से अधिक है। दूसरे शब्दों में, निर्धारिती ने 40% छूट का दावा किया। कमिश्नर ने छूट तो दी है लेकिन न्यूनीकरण नहीं। दोनों अवधारणाएँ भिन्न हैं। न्यूनीकरण की अवधारणा फैक्ट्री गेट

क्लियर किए गए माल की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है जो बिक्री डिपो से क्लियर गए माल की स्थिति से काफी अलग है।

10. इस मामले को इस न्यायालय द्वारा 31 अक्टूबर, 2007 को स्थगित कर दिया गया था। आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था कि क्या आर. एस. डब्ल्यू. एम. एल. मूल्य वृद्धि के कारण 40% की कमी का हकदार है। ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, करदाता द्वारा आयुक्त के समक्ष न्यूनीकरण का प्रश्न उठाया गया था। उस प्रश्न पर कभी निर्णय नहीं लिया गया। इन परिस्थितियों में, हमें ट्रिब्यूनल के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

11. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का कोई सटीक विज्ञान नहीं है। मूल्यांकन में कुछ मात्रा में अनुमान कार्य मौजूद है। इसलिए, मूल्यांकन नियमों द्वारा विभिन्न विधियाँ निर्धारित की जाती हैं। वास्तविक प्राप्ति का पता लगाने के लिए ये नियम निर्धारित किए गए हैं कि कौन सी प्राप्ति मूल्यांकन योग्य मूल्य का आधार बनती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्धारित विभिन्न तरीकों को एक सामान्य मूल्यांकन में परिवर्तित करना होगा। उदाहरण के लिए जैसा कि ऊपर कहा गया है नियम 6(बी)(i) "तुलनीय माल पद्धति" निर्धारित करता है नियम 6(बी)(ii) "लागत पद्धति" निर्धारित करता है और

नियम 7 जो सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन पर विचार करता है, कहता है कि मूल्यांकन अधिकारी स्वतंत्र है 1975 नियमों के नियम 1 से 6 द्वारा निर्धारित किसी भी पद्धति को लागू करने के लिए स्वतंत्र इसलिए, हम अभिसरण के पहलू पर जोर देना चाहेंगे। परिणाम में व्यापक भिन्नता स्वीकार करना संभव नहीं है, विभाग मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों को लागू कर सकता है, लेकिन अंततः उसे अभिसरण के नियम को लागू करके अनुमानित यथामूल्य मूल्य का पता लगाना होगा जो मूल्यांकन योग्य मूल्य का आधार बनेगा।

12. पूर्वोक्त कारणों से, हम विभाग द्वारा दायर इन सिविल अपीलों में कोई आधार नहीं पाते और तदनुसार कॉस्ट के संबंध में बिना किसी आदेश के इन्हें खारिज कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती रीतिका चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।